vkj- ,u- vkb- u- UPHIN/2010/32566 Mkd- ith;u- l[;k& SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक
हर ख़बर पर पैनी नज़र

o"k Z % 14 vad % 27 y[kuÅ ’kfuokj 21 vDrwcj 2023 l 27 vDrwcj 2023 rd i"B&8 eY; % ,d :i;k

मुख्यमंत्री योगी की सख्ती पर फिर चला चकबंदी विभाग में बर्खास्तगी का चाबुक

लखनऊ। चकबंदी संबंधी मामलों के निपटारे में लेटलतीफी, लापरवाही, अनियमितता पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त नाराजगी का असर दिखने लगा है। सीएम योगी के कड़े रुख के बाद चकबंदी विभाग में एक के बाद एक लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में राजस्व आयुक्त ने शुक्रवार को काम में शिथिलता बरतने पर एक चकबंदी अधिकारी, दो बंदोबस्त अधिकारी को निलंबित कर दिया है जबकि चकबन्दी अधिकारी सम्प्रति सहायक चकबन्दी अधिकारी पर विभागीय कार्यवाही करने के साथ बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं अनियमितता पर दो चकबन्दी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गयी है। चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन ने चकबंदी कार्यों में शिथिलता बरतने एवं मानक के अनुसार काम न करने पर बलिया, सीतापुर के बंदोबस्त अधिकारी अनिल कुमार और सन्तोष कुमार को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही के लिए शासन को पत्र लिया है। इसी तरह मानक के अनुसार कार्य न करने एवं शिथिलता बरतने पर मऊ के चकबंदी अधिकारी अशफाक आलम अंसारी को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। इसी तरह तत्कालीन चकबंदी अधिकारी सम्प्रति सहायक चकबन्दी अधिकारी कामता प्रसाद को सिद्धार्थनगर के ग्राम गढावर में शासकीय भूमि को क्षति पहुंचाने

में दोषी पाये जाने विभागीय कार्यवाही की संस्तुति के साथ आरोप सिद्ध होने पर बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं चकबंदी अधिकारी, अलीगढ़ बृजेश कुमार शर्मा व महराजगंज ऐश मुहम्मद को चकबन्दी क्रियाओं के दौरान गम्भीर अनियमितता पर दो पर एफआईआर दर्ज करायी गयी है। अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप चकबंदी विभाग को पारदर्शी तथा जन सामान्य के प्रति उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से चकबन्दी प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार के निर्देश दिये गये हैं। इसी के तहत चकबंदी प्रक्रिया को पूरी तरह से कम्प्यूटरीं त करते हुए इसके लिए कार्यदायी संस्था को चयनित तथा कम समय में पूरी पारदर्शिता और जन सहभागीदारी के साथ चकबंदी कार्य पूरे करने को कहा गया है ताकि वर्तमान में चकबंदी में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को सहज, सरल व प्रक्रिया को न्यूनतम कर इसकी कमियों को दूर किया जा सके। साथ ही चकबंदी कार्यों में व्याप्त व्यापक त्रुटियोंध्कमियों को तकनीकी सहायता के माध्यम से दूर कर सभी आकड़ों एवं भू–चित्र को अ नलाइन उपलब्ध कराया जाए। ऐसे में चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन ने सभी कामों के लिए नवीनतम तकनीक जैसे एआईध्एमएलध्ब्लॉक चेनध्ड्रोन रोवर आधारित सर्वेक्षण के आधार पर ई टेंडर जारी किए जाएंगे। इसी के आधार पर टेस्टिंग के रूप में एक–एक ग्राम आवंटित किया जाएगा। इससे चकबन्दी प्रक्रिया में लगने वाला समय तीन से पांच वर्ष से घट कर एक से डेढ़ वर्ष हो जाएगा।

जेल मंत्री का निर्देश, कैदियों के लिए पूजा–पाठ, फलाहार की हो व्यवस्था

लखनऊ। नवरात्रि का पर्व पूरे देश में बड़े ही धूम–धाम से मनाया जा रहा है। यूपी में भी मां दुर्गा की मूर्ति और पंडालों को स्थापित कर हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। वहीं इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार के जेल मंत्री ध र्मवीर प्रजापति ने नवरात्रि को लेकर जेल अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जेल मंत्री ने कहा कि नवरात्रि में व्रत रखने वाले कैदियों के लिए समुचित व्यवस्था की जाए और उन्होंने प्रदेश के सभी जेल अधिकारियों को जेल के अंदर ही माता रानी की पूजा पाठ की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि नवरात्रि के अवसर पर आदिशक्ति की पूजा पूरे देश में की जाती है। ऐसे में जेल में बंद कैदी भी माता रानी का व्रत रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसको लेकर सभी जेल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि व्रत रखने वाले कैदियों के लिए फलाहार की व्यवस्था कराई जाए और किसी भी प्रकार की कोई कमी न होने पाए।

अखिलेश यादव का बयान नेतृत्व की तौहीन : आचार्य प्रमोद कृष्णम

लखनऊ। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया था। इसके जवाब में अजय राय ने भी इंडिया गठबंधन के धर्म को समझाते हुए अखिलेश यादव को मीडिया के जरिये जवाब दिया था। अजय राय के लिए बोले गए शब्दों की कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आलोचना की है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर शुक्रवार को उन्होंने एक सन्देश लिखा है। जिसमें उन्होंने कहा कि हम तो अखिलेश यादव को माननीय कहते है लेकिन उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है। ये पार्टी नेतृत्व की तौहीन है।

वन अधिनियम में संशोधन की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर न्यायालय का केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को वन (संरक्षण) अधिनियम में हालिया संशोधन की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने याचिका पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय को नोटिस जारी किया। शीर्ष न्यायालय सेवानिवृत्त नौकरशाह अशोक कुमार शर्मा और अन्य की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। याचिका के जरिये वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, २०२३ की संवैधानिकता को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि नया कानून देश के पुराने वन शासन ढांचे की अनदेखी करता है। याचिका में कहा गया है, ''२०२३ का संशोधन अधिनियम मनमाने तरीके से वन भूमि में कई तरह की परियोजनाओं और गतिविधियों की अनुमति देता है और ऐसा करते हुए यह वन संरक्षण अधनियम के दायरे से उन्हें छूट देता है।'' इसमें कहा गया है, ''ये परियोजनाएं और गतिविधियां नये कानून में अस्पष्ट रूप से परिभाषित की गई हैं, और इनकी व्याख्या व्यापक जनहित की कीमत पर वाणिज्यिक हितों को पूरा करने वाले तरीके के रूप में की जाएगी।'' वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, २०२३, को लोकसभा ने २६ जुलाई को और राज्यसभा ने अगस्त में पारित किया था। इसके जरिये देश की सीमाओं के १०० किमी के भीतर की जमीन को संरक्षण कानूनों के दायरे से छूट देने का प्रावधान किया गया है तथा वन क्षेत्रों में प्राणिउद्यान, सफारी (जंगल की यात्रा) एवं पारिस्थितिकी पर्यटन की सुविधाओं की अनुमति दी गई है। याचिका के अनुसार, प्राणि उद्यान जंतुओं को कैद रखते हैं और सफारी उद्यान महज बड़े बाड़े हैं। इसमें कहा गया है कि किसी भी तरह से इसे वन्यजीव या वन्य गतिविधियों के संरक्षण के उपायों के समान नहीं बताया जा सकता।

प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली–मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर का उद्घाटन किया

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ ट्रेनों के प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया। दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का १७ किलोमीटर लंबा प्राथमिकता वाला खंड २१ अक्टूबर (शनिवार) को यात्रियों के लिए खोला जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साहिबाबाद से दुहाई डिपो को जोड़ने वाली रैपिडएक्स ट्रेन–'नमो भारत' के स्कूली बच्चों और चालक दल के साथ ट्रेन में बातचीत करते देखा गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने अप्रैल में आरआरटीएस ट्रेनों का नाम 'रैपिडएक्स' रखा था। एनसीआरटीसी भारत की पहली सेमी–हाई–स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा परियोजना लागू कर रहा है। आरआरटीएस एक नया रेल–आधारित, सेमी–हाई–स्पीड, हाई–फ्रीक्वेंसी कम्यूटर ट्रांजिट सिस्टम है जिसकी डिजाइन गति १८० किमी प्रति घंटा है। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की कि आरआरटीएस ट्रेनों को 'नमो भारत' के नाम से जाना जाएगा। मंत्री ने कहा कि करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं से जुड़ा आरआरटीएस प्रोजेक्ट का प्राथमिकता गलियारा पटरी पर आने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी २० अक्टूबर को इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देश के रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को श्नमो भारतश के नाम से जाना जाएगा। साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच आरआरटीएस कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड में पांच स्टेशन हैं। साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। दिल्ली– गाजियाबाद–मेरठ क रिडोर की आधारशिला ८ मार्च, २०१६ को प्रधान मंत्री मोदी द्वारा रखी गई थी। प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बुधवार को एक बयान में कहा था कि नए विश्व स्तरीय परिवहन बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से देश में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बदलने के उनके दृष्टिकोण के अनुरूप, आरआरटीएस परियोजना विकसित की जा रही है।

सम्पादकीय

समझ की सीमाएं स्पष्ट

समलैंगिक विवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान और वर्तमान कानून के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट से अति अपेक्षा रखने वाले आलसी कार्यकर्ता समूहों को भले इससे मायूसी हुई होगी, लेकिन कोर्ट का खुद को अपने दायरे में रखने के निर्णय से वैधानिक तौर पर असहमत होने की कम गुजाइशें ही हैं। यह कहा जा सकता है कि ऐसी अति अपेक्षाएं पैदा करने में खुद सर्वोच्च न्यायालय की भी भूमिका रही है। एक दौर में संविधान से मिले न्यायिक समीक्षा के अधिकार की बेहद व्यापक परिभाषा करते हुए उसने संविधान के बुनियादी ढांचे की अवधारणा स्थापित कर दी और फिर चूंकि मौलिक अधिकार संविधान के इस ढांचे का हिस्सा हैं, इसलिए उसने खुद को इन अधिकारों का संरक्षण घोषित कर दिया। उस दौर में उसने खुद मौलिक अधिकारों की व्यापक से व्यापक व्याख्याएं कीं। इससे एक तबके में यह धारणा बन गई कि बिना सामाजिक–राजनीतिक माहौल बनाए भी न्यायपालिका के हस्तक्षेप से समाज में बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। बहरहाल, अब उस समझ की सीमाएं स्पष्ट हो गई हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विवाह व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए समलैंगिक और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विवाह की मांग के पक्ष में उसने फैसला नहीं दिया। उसने यह उचित व्याख्या की कि स्पेशल मैरिज ऐक्ट में समलैंगिक विवाह का प्रावधान नहीं है। यह प्रावधान जोड़ना विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने यह सटीक टिप्पणी की कि अगर अदालत एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों को विवाह का अधिकार देने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा ४ में कोई शब्द जोड़ती है, तो वह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश माना जाएगी। ऐक्टिविस्ट समूह इस निर्णय से निराश हैं, तो बेहतर होगा कि वे पहले समाज में समलैंगिक विवाह के पक्ष में माहौल बनाएं। जहां तक समलैंगिकों के साथ रहने की बात है, तो न्यायपालिका पहले ही उनके बीच के यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से हटा चुकी है। चूंकि यह मुद्दा मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ था, इसलिए कोर्ट के उस फैसले का संदर्भ अलग था। वह प्रावधान ताजा निर्णय से प्रभावित नहीं होगा।

टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर आने वाले टूरिस्ट्स का वेलकम करेगा : योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के साथ ही देश की आस्था और आध्यात्मिक अभिरुचि का केंद्र रही अयोध्या नगरी अब श्रीराम मंदिर के निर्माण के साथ ही वैश्विक पटल पर व्यापक उपस्थिति दर्ज कराने को तैयार है। पीएम नरेंद्र मोदी के विजन और सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा इस विजन के क्रियान्वयन ने अयोध्या के कायाकल्प का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। श्रीराम मंदिर का निर्माण पूर्ण होने पर न केवल देश बल्कि दुनिया के विभिन्न कोनों से श्रद्धालुओं व पर्यटकों का आवागमन अयोध्या में वृहद स्तर पर बढ़ेगा। इस बात को ध्यान में रखकर योगी सरकार अयोध्या में १३० करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से ४.४० एकड़ क्षेत्र में टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर विकसित करने की कार्ययोजना पर कार्य कर रही है। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग अयोध्या में नेशनल हाइवे ३३० व नेशनल हाइवे २७ से कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर पूर्व निर्धारित जगह पर इस टूरिज्म सेंटर का विकास करने जा रही है। परियोजना के अंतर्गत टूरिस्ट सेंटर में टूरिज्म अ फिस, यात्री निवास, आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर, फूड कोर्ट वॉश पिंग मार्ट समेत तमाम कमर्शियल सेंटर्स के साथ ही पार्किंग स्पेस समेत तमाम सहूलियतों का विकास किया जाएगा। माना जा रहा है कि अगले एक से डेढ़ महीने के भीतर परियोजना धरातल पर उतर आएगी और कार्यों को मूर्त रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना को तेजी के साथ पूरा करने पर योगी सरकार का फोकस है और इसी क्रम में पर्यटन विभाग द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के जरिए डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर (डीबीएफओटी) मॉडल पर पूर्ण किया जाएगा। इस विस्तृत कार्ययोजना में उन स्थलों का भी जिक्र किया गया है जो कि वर्तमान में अयोध्या में अवस्थित हैं और प्रोजेक्ट के दौरान इनको हटाने व रीटेन करने को लेकर स्थिति भी साफ की गई है। उल्लेखनीय है कि इस विषय में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा पहले ही ई टेंडर पोर्टल के जरिए बिडिंग के आवेदन मांगे गए थे। इनमें से चार आवेदक कंपनियों का चयन कर भी लिया गया है। आगे की प्रक्रिया में इन कंपनियों को फाइनेंशियल बिडिंग का मौका दिया जाएगा और इसमें चयनित होने वाली कंपनी को फिर लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) व कंसेशन एग्रीमेंट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। अयोध्या के समेकित विकास के लिए मास्टर प्लान २०३१ के तहत इन कार्यों पूर्ण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर में कई प्रकार की सहूलियतों का विकास किया जाएगा। इनमें यात्री निवास (डॉर्मेट्रीज, बैंक्वेट व एमआईसीई फैसिलिटीज से युक्त), टूरिस्ट सेंटर (जो टूरिज्म एक्टिविटीज के हब के तौर पर कार्य करेगा) व टूरिज्म ऑफिस, कमर्शियल एरिया (आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी, शॉपिंग एरिया व क म्पलेक्स, फूड कोर्ट, कैफेटेरिया व रेस्तरां आदि), एंपीथिएटर व सुविधाओं युक्त लैंडस्केप ग्रीन पब्लिक स्पेसेस, उपयुक्त पार्किंग स्पेस व सर्विसेस (वॉटर, पावर व डीजी बैकअप) शामिल है। स्ट्रीटलाइट्स, ड्रेनेज, सिक्योरिटी, सर्विलांस फैसिलिटीज जैसे कि फायरफाइटिंग, सीसीटीवी व एचवीएसी प्रमुख हैं) का विकास प्रमुख है। उल्लेखनीय है कि अयोध्या मास्टर प्लान २०३१ के तहत निर्धारित प्लॉट लेआउट, इंटरनल रोड लेआउट यूटिलिटीज व हरित क्षेत्रों के संवर्धन को ध्यान में रखकर डेवलपर्स को पर्यटन विभाग से बिजनेस प्लान को पास कराना होगा और इसी तर्ज पर परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों को मूर्त रूप दिया जाएगा। अयोध्या टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर में कुल मिलाकर ३२७३ स्क्वेयर मीटर का बिल्ड अप एरिया होगा। इसमें शेल्टर होम, शिल्प ग्राम, टॉयलेट्स व एचएटी स्ट्रक्चर्स शामिल हैं। चौक अयोध्या रोड से आने वाली सड़क इस साइट के लिए मुख्य मार्ग के तौर पर कार्य करेगी। इस क्षेत्र में परियोजना को पूर्ण करने के लिए कुछ मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हटाना या फिर री–स्ट्रक्चर करने की भी जरूरत पड़ेगी। इसमें से रैन बसेरा व शिल्पग्राम को परियोजना के अंतर्गत क्षेत्र विस्तारीकरण के लिए हटाया जा सकता है, हालांकि इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है और फैसला होने की सूरत में लेटर ऑफ इंटेंट जारी करते वक्त इस बात को उल्लेखित भी किया जाएगा। वहीं, रामकथा पार्क (जिसमें एंपीथिएटर युक्त स्टेज होगा), क्विन हो मेमोरियल पार्क के चिह्नित क्षेत्र को रीटेन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर से कल्चरल म्यूजियम के मध्य कैनाल एक्सटेंशन पर भी कार्य हो सकता है।

एलडीए की कार्रवाई का डेवलपर व सहयोगियों ने किया विरोध

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम अमौसी एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास अवैध कालोनी का निर्माण ध्वस्त करने पहुंची तो डेवलपर व उसके सहयोगियों ने विरोध किया और नोकझोंक कर ध मकी दी। फिर भी टीम ने पुलिस बल के साथ बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त कर दिया। शुक्रवार

को उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर जोन–२ अंतर्गत थाना बिजनौर के पुराना गुरौड़ा में एलडीए की टीम पुलिस बल के साथ पहुंची। जहां एयरपोर्ट की बाउंड्री से लगी छह बीघा भूमि पर गुड्डू यादव, जितेन्द्र सैनी व अन्य द्वारा निर्माण कर कॉलोनी विकसित की जा रही थी। लेकिन, प्राधिकरण से निर्माण का ले–आउट स्वीकृत नहीं कराया था, जो विहित न्यायायल ने अवैध मानकर निर्माण ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था। इसी क्रम में सहायक अभियंता वाईपी सिंह व अवर अभियंता नागेन्द्र मिश्रा ने प्राधिकरण व स्थानीय पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर से निर्माण ध्वस्त करना शुरू किया। जिसका डेवलपर ने विरोध किया। मौके पर लेआउट व किसी तरह के साक्ष्य नहीं दिखा पाए बल्कि फोन करके अपने सहयोगियों को बुला लिया और एकजुट होकर कार्रवाई का विरोध ा किया। टीम के साथ नोकझोंक की और धमकी दी। फिर भी प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने फोर्स के साथ सख्ती दिखाते हुए निर्माण ध्वस्त कर दिया। जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि डेवलपर द्वारा सड़क, नाली, बाउन्ड्रीवाल की गई थी। साथ ही भूखंडों के डिमार्केशन के लिए ईंटों से चिनाई आदि कार्य किए गए थे जो ध्वस्त किए गए। दोबारा निर्माण करने पर इसी तरह कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

सवा करोड़ परिवारों को दिया जाएगा स्वामित्व योजना के तहत जमीन का मालिकाना हकः आदित्यनाथ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि इस साल दिसंबर तक राज्य के १.२५ करोड़ परिवारों को पीएम स्वामित्व योजना के तहत पट्टे की जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में आयोजित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने ४६७ करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाली २०८ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश ने पिछले साढ़े नौ वर्षों में परिवर्तन और विकास की एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू की है। उन्होंने कहा, इस दौरान हमने एक नए भारत का उदय देखा है, जहां समाज के हर वर्ग को जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र या के बंधनों से मुक्त होकर सम्मान के साथ प्रगति करने का अवसर दिया गया है। सबका साथ, सबका विकास की भावना– हमारा मार्गदर्शन करती है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में ७५ लाख परिवारों को उनकी जमीन पर कब्जा दिया गया है। दिसंबर २०२३ तक उत्तर प्रदेश के एक करोड़ २५ लाख परिवारों को पीएम स्वामित्व योजना के तहत पट्टे की जमीन का मालिकाना हक दिया

जाएगा। आदित्यनाथ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के जीवन में हुए सुध ारों की ओर इशारा करते हुए कहा, "वर्ष २०१७ से पहले, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पहचान के संकट का सामना करना पड़ता था। प्रध ानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के संयुक्त प्रयासों के कारण अब उन्हें पहचान के संकट से जूझना नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा, सरकार के प्रयास पूरे देश में एक भारत–श्रेष्ठ भारत के सार को दर्शाते हुए सामंजस्यपूर्ण समाज को साकार करने के लिए समर्पित हैं, जिसकी परिकल्पना बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर ने की थी।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। साथ ही बाबा विश्वनाथ धाम में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। मुख्यमंत्री ने त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए सुरक्षा बढ़ाने और सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के मामले में सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। बाद में, मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता से समझौता किए बिना इसे समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

जिसका शिलान्यास करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में कहा कि भारत की पहली रैपिड रेल सेवा 'नमो भारत' ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाना ऐतिहासिक क्षण है। वह यहां विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने वीडियो क न्फ्रेंस के जरिए बेंगलुरु मेट्रो के 'ईस्ट वेस्ट क रिडोर' के दो हिस्सों का भी औपचारिक उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक नमो भारत का संचालन शुरू हो गया है। जिसका हम शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। मोदी ने कहा कि आरआरटीएस के पहले चरण को हरी झंडी दिखाई जा चुकी हैय जब हम अगले १८ महीने में दिल्ली–मेरठ पूर्ण सेवा शुरू करेंगे तब मैं आपके बीच रहूंगा। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि भारत तभी प्रगति कर सकता है जब राज्य विकसित होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे इस आधुनिक ट्रेन से यात्रा का भी अनुभव प्राप्त हुआ है। मैंने तो बचपन रेलवे प्लेटफार्म पर बिताया है और आज रेलवे का ये नया रूप मुझे सबसे ज्यादा आनंदित करता है। उन्होंने कहा कि हमारे यहां नवरात्रि में शुभ कार्य की परंपरा है। देश की पहली नमो भारत ट्रेन को भी मां कात्यायनी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इस नई ट्रेन में ड्राइवर से लेकर सभी कर्मचारी महिलाएं हैं। ये भारत की नारीशक्ति के बढ़ते कदम का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है और स्पीड भी है ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज बेंगलुरु में मेट्रों की दो लाइनों

को भी देश को समर्पित किया गया है। इससे बेंगलुरु के आईटी हब की कनेक्टिविटी और बेहतर हुई है। बेंगलुरु में हर रोज लगभग ८ लाख लोग मेट्रो से सफर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि २१वीं सदी का हमारा भारत आज हर क्षेत्र में प्रगति की नई गाथा लिख रहा है। आज का भारत चंद्रयान को चंद्रमा पर उतारकर दुनिया में छाया हुआ है। आज का भारत जी२० का इतना शानदार आयोजन करके दुनिया के लिए आकर्षण, उत्सुकता और दुनिया का भारत के साथ जुड़ने का एक नया अवसर बन गया है। उन्होंने कहा कि आज का भारत एशियन गेम्स में १०० से ज्यादा पदक जीतकर दिखाता है। आज का भारत अपने दम पर ५जी लॉन्च करता है और उसे देश के कोने–कोने में ले जाता है। आज का भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल लेन–देन करता है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने १५०KM तक इसकी (रैपिड रेल) की यात्रा स्वयं भी की। ये सेवा दिल्ली से मेरठ की दूरी को कम कर देगी। इससे पहले मेरठ को १२ लेन के एक्सप्रेस हाईवे के साथ जोड़ा जा चुका था। १२ लेन का एक्सप्रेस हाईवे उत्तर प्रदेश में होना कभी सपना हुआ करता था लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। जिस दूरी के लिए ४ घंटे लगते थे आज मात्र ४५ मिनट में इस दूरी को तय किया जा सकता है। अब रैपिड रेल के प्रारंभ होने के साथ दिल्ली मेरठ के बीच की दूरी को उसी रूप में कम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मेट्रो निर्माण कार्यों में अन्य देश हमसे काफी आगे था लेकिन अब हम उनके बराबर ही नहीं पहुंचे हैं बल्कि हम जल्द ही उनसे आगे निकलेंगे। २–३ वर्ष में भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में से दूसरी सबसे बड़ी मेट्रो सिस्टम बनने जा रहा है। नमो भारत इस अमृतकाल में नया और टिकाऊ भविष्य बनने में हमारी मदद करेगा।

मायावती ने युद्ध को बताया मानवता के लिए विनाशकारी

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने इजराइल–हमास के बीच चल रहे युद्ध पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने अपने लिखे संदेश में युद्ध को मानवता के लिए विनाशकारी कहा है। साथ ही यूक्रेन में हुए युद्ध के चलते आई कई वैश्विक समस्याओं के बारे में भी उन्होंने याद दिलाया है। अपने संदेश में मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिखे श्जीपे पे दवज ंद मतं वू्तश कोट का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के समय तत्कालीन पश्चिमी देशों के नेताओं ने इसपर सहमति दी थी। उन्होंने लिखा कि भारत को अपने इसी स्टैंड पर कायम रहना चाहिए।

सरकारी जमीनों से हटाया गया अतिक्रमण

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान जिला प्रशासन की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है। इसी के तहत शुक्रवार को सरोजनीनगर, मलिहाबाद और बीकेटी इलाके में स्थित सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। यह वह जमीने हैं जो कि अभिलेखों में नवीन परती, बंजर, ऊसर, चारागाह और तालाब के तौर पर दर्ज है। डीएम सूर्य पाल गंगवार ने बताया है कि बताया जिले में सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने का सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज तहसील सरोजनी नगर में बेंती गांव में चकमार्ग पर किये गये अवैध कब्जा हटाया गया। वहीं मलिहाबाद स्थित टिकरी खुर्द

में रास्ते से अतिक्रमण हटाया गया। इसके अलावा ढकवा गांव में तालाब की भूमि पर हुये अतिक्रमण को भी हटा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि शासकीय भूमियों पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नही किया जाएगा। आगे भी लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खां, पत्नी और बेटे को सात साल की जेल

रामपुर की एक अदालत ने बुधवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को वर्ष २०१६ के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी ठहराते हुए सात साल की जेल की सजा सुनाई। समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने अदालत के इस निर्णय के बाद आरोप लगाते हुए कहा कि खां के धर्म की वजह से उनके साथ अन्याय हो रहा है। अभियोजन पक्ष के वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया, एमपीं एमएलए अदालत के मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात साल की सजा सुनायी और ५० हजार रुपये जुर्माने का जुर्माना भी लगाया। फैसले के बाद, तीनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया और अदालत से ही जेल भेज दिया गया। अदालत के आज फैसला सुनाये जाने के मद्देनजर शहर में व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त किये गये थे। सक्सेना ने बताया कि रामपुर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने तीन जनवरी २०१६ को गंज पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि खां और उनकी पत्नी तजीन ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम को दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने में मदद की थी। इसमें कहा गया था कि इनमें से एक प्रमाणपत्र लखनऊ से जबकि दूसरा रामपुर से बनवाया गया था। उन्होंने बताया कि सभी अभियुक्तों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा ४२० में तीन वर्ष का कारावास और १०–१० हजार रुपये जुर्माने, धारा ४६७ में सात वर्ष की कैद और १५–१५ हजार रुपये जुर्माना, धारा ४६८ में तीन वर्ष का कारावास और १०–१० हजार रुपये जुर्माना, धारा ४७१ में दो वर्ष का कारावास और १०–१० हजार रुपये जुर्माना तथा धारा १२०ेंबी में एक वर्ष कारावास और पांच–पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी है। सक्सेना ने बताया कि इस तरह अधिकतम सजा सात साल है जो कि सात वर्ष माना जाएगा और जुर्माने की रकम ५० हजार रुपये मानी जाएगी। सजा सुनाए जाने के बाद बाहर निकले आजम खां से जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ''आज फैसला हुआ है, फैसले में और इंसाफ में फर्क होता है।'' सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में रामपुर की अदालत द्वारा सात साल की सजा सुनाये जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए

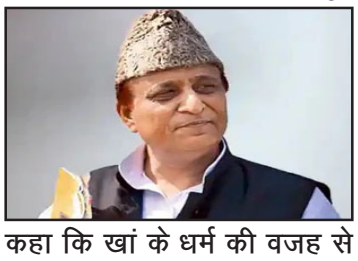

कहा कि खां के धर्म की वजह से उनके साथ अन्याय हो रहा है। सपा द्वारा सोशल मीडिया मंच एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किये गये एक वीडियो में यादव ने कन्नौज में संवाददाताओं से बातचीत में खां और उनके परिजन को सजा सुनाये जाने के सवाल पर कहा, मुझे तो यह लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके (आजम) साथ इतना अन्याय न हो रहा हो। सबको यकीन है और सब जानते हैं कि उन पर इसीलिये अन्याय हो रहा है कि उनका धर्म दूसरा है। अभियोजन पक्ष के वकील सक्सेना ने बताया कि रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि एक जनवरी १९९३ बताई गई थी। उन्होंने बताया कि वहीं दूसरे प्रमाण पत्र से पता चला कि उनका जन्म ३० सितंबर, १९९० को लखनऊ में हुआ था। वर्ष २०२२ के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर स्वार सीट से जीतने वाले अब्दुल्ला को वर्ष २००८ में एक लोक सेवक को गलत तरीके से रोकने के लिए उस पर हमला करने के आरोप में मुरादाबाद की एक अदालत ने पहले ही दोषी ठहराया था।इस साल फरवरी में दोषी ठहराए जाने और दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के दो दिन बाद अब्दुल्ला को उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि अब्दुल्ला ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिये उच्च न्यायालय में अपील की थी जिसे नामंजूर कर दिया गया था। अदालत के निर्णय के बाद आजम, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को अदालत से सीधे जेल ले जाया गया। रामपुर जेल के मुख्य द्वार के सामने उन्होंने संवाददाताओं से कहा, पूरे शहर को मालूम था कि क्या फैसला होना है।

लखनऊ में पार्टी करने पहुंचे नीदरलैंड के क्रिकेटर, समिट बिल्डिंग के सामने हुए स्पॉट

लखनऊ। नीदरलैंड के खिलाड़ी गुरुवार रात को राजधानी के गोमतीनगर इलाके की समिट बिल्डिंग के सामने स्पॉट हुए। ब्लैक C# हाउस क्लब में खिलाडियों ने जमकर पार्टी की। बता दें कि कल २१ अक्टूबर को इकाना स्टेडियम में श्रीलंका के साथ नीदरलैंड टीम का मुकाबला है। हाल ही में नीदरलैंड ने अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को मात दी है। वान डेर मर्व के साथ टीम के अन्य दो खिलाड़ी और एक भारतीय प्रतिनिधि क्लब पहुंचे। खिलाडियों को कई क्लब और रेस्टोरेंट अपने यहाँ आने का आग्रह करने लगे। लेकिन उन्होंने

पार्टी के लिए ब्लैक C# हाउस क्लब का ही चयन किया। क्लब में डांडिया का भी आयोजन किया गया था।

सीवर सफाई के दौरान मरने वालों के परिजनों को ३० लाख रुपये का मुआवजा देने का न्यायालय का आदेश

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने देशभर में हाथ से मैला उठाने (मैनुअल स्केवेजिंग) की प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने का निर्देश केंद्र और राज्य सरकारों को देते हुए शुक्रवार को कहा कि इस प्रथा से जुड़े लोग लंबे समय से 'बंधुआ' बनकर रह रहे हैं और वे व्यवस्थित रूप से अमानवीय परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। शीर्ष अदालत ने हाथ से मैला उठाने का काम करने वाले लोगों के लाभ के लिए कई दिशानिर्देश पारित करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से सीवर की सफाई के दौरान मरने वालों के परिजनों को मुआवजे के रूप में ३० लाख रुपये देने को कहा। न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने हाथ से मैला साफ करने के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा, ''हमारी लड़ाई सत्ता की ताकत के लिए नहीं है। यह आजादी की लड़ाई है। यह मानव व्यक्तित्व को पुनः प्राप्त करने की लड़ाई है।'' न्यायमूर्ति भट ने इस दौरान बाबा साहेब बी. आर. आंबेडकर को उद्धृत किया। पीठ ने कहा कि सीवर की सफाई के दौरान स्थायी दिव्यांगता का शिकार होने वालों को न्यूनतम मुआवजे के रूप में २० लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा और किसी अन्य प्रकार की चोट के लिए उसे १० लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। पीठ ने निर्देश दिया कि सरकारी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करना चाहिए कि इस प्रथा का पूरी तरह उन्मूलन हो। पीठ ने 'हाथ से मैला उठाने वालों के रोजगार पर प्रतिबंध और उनका

पुनर्वास अधिनियम, २०१३' के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को १४ दिशानिर्देश जारी किए। पीठ की ओर से न्यायमूर्ति भट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अधिकारियों को पीड़ितों और उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए उपाय करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों के परिजनों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए और कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाए। न्यायमूर्ति भट ने कहा, ''यदि आपको वास्तव में सभी मामलों में समान होना है, तो संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद १५(२) जैसे मुक्तिदायक प्रावधानों को लागू करके समाज के सभी वर्गों को जो प्रतिबद्धता दी है..., हममें से प्रत्येक को अपने वादे पर खरा उतरना होगा। केंद्र और राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि हाथ से मैला साफ करने की प्रथा पूरी तरह खत्म हो। संविधान के अनुच्छेद १५(२) में कहा गया है कि सरकार किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी।'' न्यायमूर्ति भट ने कहा कि सच्चे भाईचारे को साकार करना सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा, ''यह अकारण नहीं है कि हमारे संविधान में गरिमा और भाईचारे के मूल्य पर बहुत जोर दिया गया है। लेकिन इन दोनों के लिए, अन्य सभी स्वतंत्रताएं कल्पना हैं। अपने गणतंत्र की उपलब्धियों पर गर्व करने वाले हम सभी को आज जागना होगा, ताकि वह अंधेरा छंट जाए।'' पीठ ने जनहित याचिका की आगे की सुनवाई के लिए एक फरवरी, २०२४ की तारीख निर्धारित की है। जुलाई २०२२ में लोकसभा में उद्धृत सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में भारत में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कम से कम ३४७ लोगों की मौत हुई, जिनमें से ४० प्रतिशत मौतें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली में हुईं।

दो और कोविड योद्धाओं के परिजनों को मिलेगी एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि : केजरीवाल

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महामारी के दौरान जान गंवाने वाले दो और कोविड योद्धाओं के परिवारों को सरकार की ओर से एक–एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने की शुक्रवार को घोषणा की।

मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद केजरीवाल ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, पूरे देश में दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसने महामारी के दौरान जान गंवाने वाले कोविड योद्धाओं के परिवारों को एक–एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि मुहैया कराकर उनके त्याग को सम्मानित किया है। दिल्ली में कई चिकित्सकों, स्वास्थ्य देखभाल कर्मी, पुलिस अधिकारियों, साफ–सफाई कर्मी, पैरा मैडिकल कर्मी और स्वंयसेवकों ने जान गंवाई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालिया मंत्रिमंडल की एक बैठक में कोरोना योद्धाओं की सूची में दो और नामों को शामिल किया गया। केजरीवाल ने कहा कि इनमें से एक सतपाल हैं, जो साकेत में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल स्टोर पर तैनात थे और यह एक उच्च जोखिम वाला क्षेत्र था। केजरीवाल ने कहा, वह दिल्ली की ४० डिस्पेंसरियों में दवाएं भेजते थे, जहां हजारों स्वास्थ्यकर्मी और मरीज उन दवाओं पर निर्भर रहते थे। सक्रिय ड्यूटी के दौरान, वह कोविड–१९ से संक्रमित हो गए और २८ नवंबर, २०२० को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि अन्य कोविड योद्धा दिल्ली पुलिस के सिपाही अमित कुमार थे, जो भरत नगर थाने में तैनात थे। केजरीवाल ने कहा, लॉकडाउन के दौरान उनकी ड्यूटी दीप चंद बंधु अस्पताल के आसपास वाले अत्यधिक जोखिम वाले संक्रामक क्षेत्र में थी। ड्यूटी के दौरान उन्हें भी कोरोना हो गया और पांच मई, २०२० को उनकी मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार पहले ही ६२ कोविड योद्धाओं के परिवारों को एक–एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान कर चुकी है।

ऑपरेशन चक्र २: संदिग्ध चीनी नागरिक से जुड़े साइबर 'घोटाले' की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ली

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)ने एक संदिग्ध चीनी नागरिक से जुड़े कथित घोटाले की जांच अपने हाथ में ले ली है, जिसमें भारतीय नागरिकों को निवेश, ऋण और नौकरी के अवसरों के नाम पर निशाना बनाया गया था और उनकी जमा राशि का १३७ से अधिक मुखौटा कंपनियों के जरिये गबन किया गया। एजेंसी ने कहा कि बेंगलुरु स्थित एक 'पेआउट मर्चेंट' की भूमिका केंद्र में है जिसके संबंध संदिग्ध चीनी नागरिक से था और वह जांच के दायरे में है। सीबीआई ने यहां जारी बयान में कहा, ''धोखाधड़ी के केंद्र में रहने वाला यह 'मर्चेंट' लगभग १६ अलग–अलग बैंक खातों को नियंत्रित करता था, जहां ३५७ करोड़ रुपये (लगभग) की भारी–भरकम राशि जमा की गई थी। फिर इस राशि को विभिन्न खातों में भेजा गया...।''साइबर अपराधियों के खिलाफ शुरू 'ऑपरेशन चक्र –२' के तहत, केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाल ही में बेंगलुरु, कोचिन और गुरुग्राम में तलाशी ली थी और इस दौरान मुखौटा कंपनियों के निदेशकों की कथित संदिग्ध गतिविधियों को उजागर करने वाले सबूत मिले थे। बयान के अनुसार, एजेंसी ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई४सी) की सूचना के आधार पर घोटाले के संबंध में मामला दर्ज किया, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बयान के मुताबिक यह मामला ''निवेश, ऋण और नौकरी के अवसरों के

नाम पर विदेशी घोटालेबाजों द्वारा भारतीय नागरिकों के खिलाफ किए जा रहे परिष्कृत, संगठित साइबर अपराध'' से संबंधित है। सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया, ''जालसाजों ने कथित तौर पर पोंजी योजनाओं और बहु–स्तरीय मार्केटिंग पहल के माध्यम से आकर्षक अंशकालिक नौकरियों के वादे के साथ पीड़ितों को लुभाने की कोशिश की और इसके लिए विभिन्न सोशल मीडिया और विज्ञापन मंचों, चौट एप्लिकेशन और एसएमएस का सहारा लिया।'' प्रवक्ता ने बयान में कहा,''यूपीआई खातों के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से गलत तरीके से कमाए गए धन को सफेद किया गया, जो अंततः गलत प्रमाण–पत्रों के जरिये इस राशि को क्रिप्टोकरेंसी या सोने में परिवर्तित किया गया।'' बयान के मुताबिक सीबीआई ने १३७ मुखौटा कंपनियों की पहचान की है, जो ज्यादातर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, बेंगलुरु के साथ पंजीकृत हैं, जिनका इस्तेमाल भोले–भाले निवेशकों से इकट्ठा किए गए पैसे को निकालने के लिए किया जाता था। ऑपरेशन के तहत, सीबीआई ने इंटरपोल के माध्यम से सिंगापुर पुलिस की खुफिया जानकारी के आधार पर एक और मामला भी दर्ज किया है जिसमें दक्षिण पूर्व एशियाई देश के ४०० नागरिकों को भारत स्थित साइबर अपराधियों द्वारा निशाना बनाया गया था। एजेंसी ने सिंगापुर के नागरिकों के खिलाफ ३०० साइबर धोखाधड़ी का पता लगाया है, जिसमें १० राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैले १०० से अधिक भारतीय बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया। अ परेशन चक्र–२ के तहत सीबीआई ने इन आरोपियों के ठिकानों की तलाशी ली।

कांग्रेस बिना समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में भाजपा को नहीं हटा सकती : शिवपाल

लखनऊ। मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं बन पाने के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तनातनी की स्थिति है। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप किया जा रहे हैं। इन सबके पीछे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस बिना समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में भाजपा को किसी भी कीमत पर नहीं हरा सकती। शिवपाल ने कहा कि यदि वे (कांग्रेस) भारत गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं और भाजपा को हराना चाहते हैं, तो उन्हें सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाना चाहिए। तभी भाजपा को हटाया जा सकता है। शिवपाल ने कांग्रेस पर कहा कि उन्हें मध्य प्रदेश में किए गए वादे पर कायम रहना चाहिए था, तभी इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और बीजेपी हारेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इन छोटे नेताओं (अजय राय) पर रोक लगानी चाहिए। अगर **INDIA** गठबंधन को मजबूत करना है और भाजपा को हटाना है तो सभी विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करके गठबंधन को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जो वादा किया था, उसपर अडिग रहना चाहिए था... कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, इन्हें सबको मिलाकर चलना पड़ेगा... कांग्रेस बिना समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में भाजपा को नहीं हटा सकती है। इस बीच, कांग्रेस पर लगे विश्वासघात के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर एमपी कांग्रेस प्रमुख कमल नाथ ने गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'अरे भाई छोड़ो अखिलेश वखिलेश।' उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हवा

चल रही है। उन्होंने कहा कि मौहाल बहुत अच्छा है। लोग हमें फोन करके बता रहे हैं कि लोगों में उत्साह है। हम अपनी उम्मीद से भी बेहतर संख्या से जीतेंगे। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने सपा पर 'प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से' भाजपा की मदद करने का आरोप लगाया दिया। अजय राय ने कहा कि अखिलेश यादव जी, जनता देख रही है कि बीजेपी के साथ कौन है। घोसी उपचुनाव में हमने उन्हें (सपा को) समर्थन दिया और वे जीत गये। वहीं, उत्तराखंड में बागेश्वर उपचुनाव हुए। उन्होंने वहां अपना उम्मीदवार खड़ा किया और बीजेपी जीत गई और कांग्रेस हार गई।

राहुल ने कहा- कांग्रेस में शामिल होने के लिए भाजपा नेताओं की लगी है कतार

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक रैली में तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं की तुलना 'बॉलीवुड नायकों' से करते हुए कहा कि वे (भाजपा नेता) जो पहले इतराते थे, अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए लाइन लगाए खड़े हैं। गांधी ने शुक्रवार को समाप्त हुए अपने तीन–दिवसीय तूफानी दौरे पर किसानों को बेहतर समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने, 'भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस), भाजपा और ऑल इंडिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमीन' (एआईएमआईएम) की कथित सांठगांठ तथा राज्य के स्वामित्व वाली सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) जैसे विभिन्न मुद्दे उठाये। निजामाबाद और जगतियाल जिलों में अलग–अलग बैठकों में गांधी ने तेलंगाना भावना को जागृत करते हुए कहा कि उनकी मां एवं पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ही थीं, जिन्होंने नये राज्य का निर्माण कराया था। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मां ने इसका समर्थन नहीं किया होता, तो यह नया दक्षिणी राज्य नहीं बन पाता। उन्होंने कहा, ''यहां (तेलंगाना में) लड़ाई कांग्रेस और बीआरएस के बीच है। पहले भाजपा नेता यहां ब लीवुड हीरो की तरह घूमते थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि उनकी गाड़ी के चारों पहिये कब निकल गए। आज भाजपा नेता कांग्रेस में शामिल होने के लिए कतार में खड़े हैं। (लेकिन) हम उन्हें नहीं चाहते। उन्होंने तेलंगाना की भावनाओं को जागृत करने की कोशिश करते हुए कहा, ''सोनिया जी ने तेलंगाना राज्य बनाने में आपकी मदद की और मैं यह भी कह सकता हूं कि अगर सोनिया गांधी ने मदद नहीं की होती, तो अलग तेलंगाना नहीं बनता। सोनिया गांधी जी दोराला (सामंतों) का तेलंगाना नहीं, बल्कि प्रजाला (जनता का) तेलंगाना चाहती थीं।''राज्य में पार्टी की चल रही विजयभेरी यात्रा के दौरान रैलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ३० नवंबर के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आती है, तो यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनके द्वारा उगाई जाने वाली

प्रत्येक फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से ५०० रुपये अधिक मिलें। गांधी ने कहा कि इसके अलावा, कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि हल्दी उत्पादक किसानों को १२,००० रुपये से १५,००० रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य मिले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्षेत्र में चीनी मिलों को भी पुनर्जीवित करेगी। गांधी ने एक बार फिर कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह तेलंगाना सहित पूरे देश में जातिगत जनगणना कराएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन शासन द्वारा कराई गई जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक न करने का आरोप लगाया। गांधी ने कहा, ''कांग्रेस दिल्ली (केंद्र) में सत्ता में आने के बाद पिछले आंकड़े जारी करेगी और नयी जाति–आधारित जनगणना भी कराएगी।'' उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर पार्टी तेलंगाना में भी जातिगत जनगणना कराएगी। बीआरएस, भाजपा और एआईएमआईएम पर निशाना साधते हुएवायनाड सांसद ने कहा कि तीनों दल आपसी मिलीभगत से काम करते हैं और मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाला राजनीतिक दल संसद में भगवा पार्टी का समर्थन करता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि राव के खिलाफ न तो कोई सीबीआई जांच हुई, न ईडी या आईटी जांच हुई, जबकि देश में विपक्षी नेताओं के खिलाफ कई मामले दर्ज किये गये हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में आगामी चुनाव में सत्तारूढ़ बीआरएस और कांग्रेस के बीच लड़ाई है और उनकी पार्टी बीआरएस को हरा देगी।उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आगामी चुनावों में भगवा पार्टी को हरा देगी। उन्होंने तेलंगाना के लोगों से चुनाव में कांग्रेस को वोट देने का आग्रह भी किया। तेलंगाना में सत्ता में आने की उम्मीद कर रही कांग्रेस पार्टी ने राज्य में ३० नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाद्रा के साथ अपना चुनाव अभियान शुरू किया।

मामलों के निपटारे में देरी से वादियों का न्यायिक व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगाः उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि यदि कानूनी प्रक्रिया कच्छप गति से आगे बढ़ती है तो न्यायिक व्यवस्था से वादकारियों का मोहभंग हो सकता है। इसके साथ ही न्यायालय ने पुराने मामलों की तेजी से सुनवाई और निपटान सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किये, जिनमें से कुछ उच्च न्यायालयों के लिए भी हैं। न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने लंबित मामलों को लेकर राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के देशव्यापी आंकड़ों का हवाला दिया और कहा कि इस मुद्दे से निपटने के लिए 'बार एवं बेंच' के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। पीठ ने कहा, ''कानूनी प्रक्रिया जब कच्छप गति से आगे बढ़ती है तो वादियों का मोहभंग हो सकता है। एनजेडीजी के आंकड़ों के अनुसार, कुछ मुकदमे ५० साल से लंबित हैं और इसे लेकर हमने अपनी पीड़ा व्यक्त की है।'' पीठ ने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों केकुछ पुराने मामलों का भी उल्लेख किया, जिनका ६५ साल से अधिक समय में भी निपटारा नहीं हो सका है। न्यायमूर्ति कुमार ने कहा, ''जब (मामलों के निपटारे में) देरी जारी रहेगी, तो वादकारियों का न्यायिक प्रणाली से भरोसा उठ जाएगा।'' पीठ ने कहा कि वादियों को बार–बार स्थगन मांगने में सावध ानी बरतनी चाहिए। न्यायमूर्ति कुमार ने ११ निर्देश जारी करते हुए

कहा, ''अब समय आ गया है कि न्याय किसी का इंतजार नहीं करता। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध किया गया है और निचली अदालतों को निर्देश जारी किये गये हैं।'' फैसला सुनाते वक्त निर्देशों का उल्लेख नहीं किया गया और इसके बारे में तभी पता चलेगा, जब संबंधित निर्णय शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। पीठ ने कहा, ''संबंधित राज्यों के (उच्च न्यायालयों के) मुख्य न्यायाधीशों द्वारा गठित समिति दो महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी और संबंधित अदालतों को उचित सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश देगी, साथ ही, वैसे पुराने मामलों की भी निगरानी करेगी जो पांच साल से अधिक समय से लंबित हैं।'' पीठ ने शीर्ष अदालत के महासचिव को निर्देश दिया कि वह फैसले की प्रति उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को विचारार्थ और उचित कदम उठाने के लिए जारी करें। न्यायमूर्ति कुमार ने कहा, ''हमने लंबित मामलों के सभी आंकड़ों का संज्ञान ले लिया है... और थोड़ी पीड़ा के साथ, हमने कहा है कि इस पर 'बार एवं बेंच' दोनों को ध्यान देना होगा।'' यह फैसला यशपाल जैन की याचिका पर आया, जिन्होंने एक दीवानी मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के २०१६ के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। तैंतालीस साल पहले वहां की एक स्थानीय अदालत में शुरू हुआ यह विवाद अब भी जारी है। पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और निचली अदालत से जैन की याचिका पर छह महीने के भीतर फैसला करने को कहा।

इंडिया में रार पर भड़के अखिलेश ने कहा, अगर कांग्रेस का यही व्यवहार रहा तो उन पर कौन करेगा भरोसा

लखनऊ। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तनातनी बढ़ गई है। इंडिया गठबंधन में होने के बाद भी दोनों दलों के बीच राज्य में गठबंधन नहीं हो सका है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगा रहे है। अखिलेश ने कहा कि अगर कांग्रेस (मध्य प्रदेश में) सीटें नहीं देना चाहती थी तो उन्हें यह पहले ही कहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि भारत गठबंध ान राष्ट्रीय स्तर पर (संसदीय) चुनाव के लिए है। अगर कांग्रेस का यही व्यवहार रहा तो उन पर भरोसा कौन करेगा? मन में भ्रम लेकर भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे तो सफल नहीं होंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को जब समर्थन की जरूरत थी उस समय समाजवादी पार्टी ने उसका समर्थन किया। जिस समय कांग्रेस के नेताओं से बात हुई उस समय मैंने कहा था कि जो हमसे सहयोग लेना चाहो ले लो, हम भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उस समय रात १ बजे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद हमें आश्वासन दिया गया कि विध ानसभा चुनाव में हमें लगभग ६ सीटें दी जा सकती हैं लेकिन जब कांग्रेस की सूची आई तो हमारी जीती हुई सीटों पर भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। मजबूरी में समाजवादियों को अपने मजबूत क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते हुए चुनाव लड़ाना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी केवल उन्हीं सीटों पर लड़ेंगे जहां हमारा संगठन है और जहां से हम भाजपा को हराना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बातचीत शुरू हुई थी। हालांकि किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही यह खत्म हो चुकी है। दोनों राजनीतिक दलों ने अपने–अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। इसके बाद दोनों ओर से शब्द बाण भी एक–दूसरे के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि सपा–कांग्रेस

गठबंधन पर ब्रेक लगने से अखिलेश यादव नाराज है। उन्होंने यह तक कह दिया है कि मध्य प्रदेश में अगर यह गठबंधन नहीं हुआ तो भविष्य में प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं होगा। कमलनाथ ने कहा कि विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' का ध्यान लोकसभा चुनाव पर है और अगर यह गठबंधन मध्य प्रदेश विध ानसभा चुनाव में होता है तो अच्छा होता। कमलनाथ ने कहा कि चुनावी साझेदारी (सहयोगियों के साथ) में कुछ जटिलताएं हैं क्योंकि कांग्रेस को स्थानीय स्थिति पर विचार करना होगा। आप भी वहा अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में सपा–कांग्रेस गठबंधन नहीं होने के बाद जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी भी कांग्रेस पर आक्रामक हो गई है और इसका सीधा कनेक्शन राजस्थान से है।

सीबीआई अधिकारी बनकर ठगी करने का आरोपी गिरफ्तार

मुंबई। पुलिस ने खुद को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का अधिकारी बताने और एक टैक्सी चालक से उसके बेटे को जांच एजेंसी में नौकरी दिलाने का वादा कर ठगी करने के आरोप में एक व्यक्ति को यहां गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि शिकायतकर्ता कोल्हापुर के रहने वाले आरोपी को दक्षिण मुंबई में लेकर जा रहा था जब उसने उसे फोन पर सीबीआई द्वारा मारे छापों और गिरफ्तारियों के बारे में बात करते हुए सुना। उससे प्रभावित होकर उसने आरोपी के साथ बातचीत शुरू की जिसने बताया कि वह चालक के बेटे को एक लाख रुपये के बदले में सीबीआई में नौकरी दिला सकता है। पुलिस ने बताया कि टैक्सी चालक ने उसे १५,००० रुपये दे दिए और कहा कि बाकी के पैसे वह बाद में देगा। आरोपी को उसके गंतव्य पर छोड़ने के बाद उसे शक हुआ और वह मरीन ड्राइव पुलिस थाने गया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

नहीं जागे तो चांद पर क्या होगा प्रज्ञान और विक्रम का हाल, किस खतरे का है डर?

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान–३ फिलहाल चंद्रमा पर निष्क्रिय अवस्था में है। चंद्रयान–३ २३ अगस्त को चंद्रमा पर उतरा और रोवर तैनात करने के साथ–साथ कई प्रयोग किए। फिर ये हमेशा के लिए स्लीप मोड में चला गया है। जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाता, अंतरिक्ष यान कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा और हमेशा चंद्रमा की सतह पर ही रहेगा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा है कि विक्रम लैंडर अपना काम बहुत अच्छे से करने के बाद चंद्रमा पर खुशी से सो रहा है। जैसे ही अंतरिक्ष यान स्लीप मोड में रहता है, उसे नए खतरों का सामना करना पड़ता है, जो चंद्रमा के बाहर से आते हैं। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को निष्क्रिय कर दिया गया है और अब चंद्रमा पर उनके सामने सबसे बड़ा खतरा सूक्ष्म उल्कापिंड प्रभावों का हैं। ये दोनों माइक्रोमीटरोइड्स से प्रभावित हो सकते हैं। इसरो को इसके बारे में पता था क्योंकि अतीत में मिशनों को इसी तरह का नुकसान उठाना पड़ा था, जिसमें

अपोलो अंतरिक्ष यान भी शामिल था जो चंद्रमा की सतह पर रह गया था। मणिपाल सेंटर फॉर नेचुरल साइंसेज के प्रोफेसर और निदेशक डॉ. पी. श्रीकुमार ने बताया कि चूंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल या ऑक्सीजन नहीं है। इसलिए अंतरिक्ष यान के क्षरण का कोई खतरा नहीं है। हालाँकि, जो देखा जाना बाकी है वह सूक्ष्म उल्कापिंड प्रभाव हैं जो लंबी चंद्र रात के ठंडे तापमान के अलावा अंतरिक्ष यान को और नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है इसलिए सूर्य से लगातार विकिरण बमबारी भी हो रही है। इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है। हालांकि, हमें अभी तक पता नहीं है कि क्या होगा क्योंकि इसके आसपास ज्यादा डेटा नहीं है। चंद्रमा की धूल भी लैंडर और रोवर की सतह तक पहुंच जाएगी। पृथ्वी की धूल के विपरीत, चंद्रमा पर हवा की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा की धूल सामग्री से चिपक सकती है। यह देखने के लिए डेटा उपलब्ध है कि चंद्र अंतरिक्ष यान पर धूल कैसे जगह घेरती है, जैसा कि अपोलो मिशन के दौरान देखा गया था। डॉ. पी. श्रीकुमार ने कहा कि अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा की सतह पर छोड़े गए चंद्र परावर्तकों को ढंकते हुए धूल की परतें देखी गई हैं, तो हमें इसके बारे में कुछ पता है।

परीक्षण यान मिशन के साथ मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाले पहले उड़ान कार्यक्रम के लिए इसरो तैयार

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) शनिवार को एकल–चरण तरल प्रणोदक वाले रॉकेट के प्रक्षेपण के जरिये मानव को अंतरिक्ष में भेजने के अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 'गगनयान' की दिशा में आगे बढ़ेगा। इस दौरान, प्रथम 'क्रू मॉड्यूल' के जरिये अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का परीक्षण किया जाएगा। इसरो का लक्ष्य तीन दिवसीय गगनयान मिशन के लिए मानव को ४०० किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इसरो के अन्य मिशन से इतर अंतरिक्ष एजेंसी अपने परीक्षण यान एकल चरण प्रणोदन वाले तरल रॉकेट (टीवी–डी१) के सफल प्रक्षेपण का प्रयास करेगी, जिसे २१ अक्टूबर को सुबह आठ बजे इस अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम प्रक्षेपण स्थल से उड़ान भरने के लिए निर्धारित किया गया है। रॉकेट ३४.६ मीटर

लंबा है और इसका भार ४४ टन है। टीवी–डी१ उड़ान एक 'सिम्युलेटेड थर्मल सुरक्षा प्रणाली' के साथ एकल–दीवार वाली बिना दबाव वाली एल्यूमीनियम की संरचना है। परीक्षण वाहन डी१ मिशन का लक्ष्य नए विकसित परीक्षण वाहन के साथ चालक बचाव प्रणाली की रॉकेट से अलग होने और सुरक्षित वापसी की क्षमता को प्रदर्शित करना है। मिशन के कुछ उद्देश्यों में उड़ान प्रदर्शन और परीक्षण वाहनों का मूल्यांकन, चालक बचाव प्रणाली, क्रू मॉड्यूल विशेषताएं, और अधिक ऊंचाई पर गति नियंत्रण शामिल हैं। इस अभियान के माध्यम से, वैज्ञानिकों का लक्ष्य चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिन्हें वास्तव में गगनयान मिशन के दौरान एलवीएम–३ रॉकेट से 'क्रू मॉड्यूल' में भेजा जाएगा। शनिवार को टीवी–डी१ के परीक्षण के साथ वैज्ञानिकों ने परीक्षणों की एक श्रृंखला भी तैयार की है।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने दो उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने दो उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। बृहस्पतिवार रात को सपा ने तीसरी सूची जारी करने के साथ ही अब तक अपने ३३ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश में १७ नवंबर को विधानसभा की २३० सीटों के लिए चुनाव होना है। कांग्रेस ने १४४ उम्मीदवारों की पहली पहली सूची गत रविवार को और दूसरी सूची बृहस्पतिवार देर रात को जारी की। कांग्रेस अब तक कुल २२६ उम्मीदवारों

की घोषणा कर चुकी है। दोनों पार्टियों के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी मप्र में सपा के लिए छह सीटें छोड़ने को तैयार हुई थी लेकिन दोनों के बीच सहमति नहीं बन सकी। अपनी तीसरी सूची में सपा ने सीधी जिले के चुरहट और छतरपुर जिले के चांदला (अनुसचित जाति आरक्षित) निर्वाचन क्षेत्र से क्रमशः राजेंद्र प्रसाद पटेल और पुष्पेंद्र कुमार अहिरवार को नामित किया है। राज्य में २१ अक्टूबर से नामांकन पत्र दाखिल करना शुरू हो जाएगा।

अदभुत चट्टानः गुप्त खजानों वाला चट्टान

अमरेन्द्र सहाय अमर

वैज्ञानिकों ने ४,००० साल पुरानी प्राचीन पत्थर की कलाकृति का रहस्य सुलझाने का दावा किया है. उनका कहना है कि पत्थर पर बने रहस्यमयी निशान असल में किसी 'गुप्त खजाने' का नक्शा हो सकते हैं.वैज्ञानिक इसमें बनी नक्काशी के छिपे रहस्य को जानने में लगे हुए थे वैज्ञानिकों ने ४,००० साल पुरानी प्राचीन पत्थर की कलाकृति का रहस्य सुलझाने का दावा किया है. उनका कहना है कि पत्थर पर बने रहस्यमयी निशान असल में किसी 'गुप्त खजानेश'का नक्शा हो सकते हैं. 'सेंट–बेलेक स्लैब' के नाम से जाने जाने वाले इस कांस्य युग के पत्थर की पहचान शोधकर्ताओं ने २००१ में यूरोप के सबसे पुराने मानचित्र के रूप में की थी. तभी से वह इसमें बनी नक्काशी के छिपे रहस्य को जानने में लगे हुए थे. एक रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांस में खोए हुए स्मारकों की खोज के लिए वैज्ञानिक अब स्लैब को 'खजाने का नक्शा' मान रहे हैं. वेस्टर्न

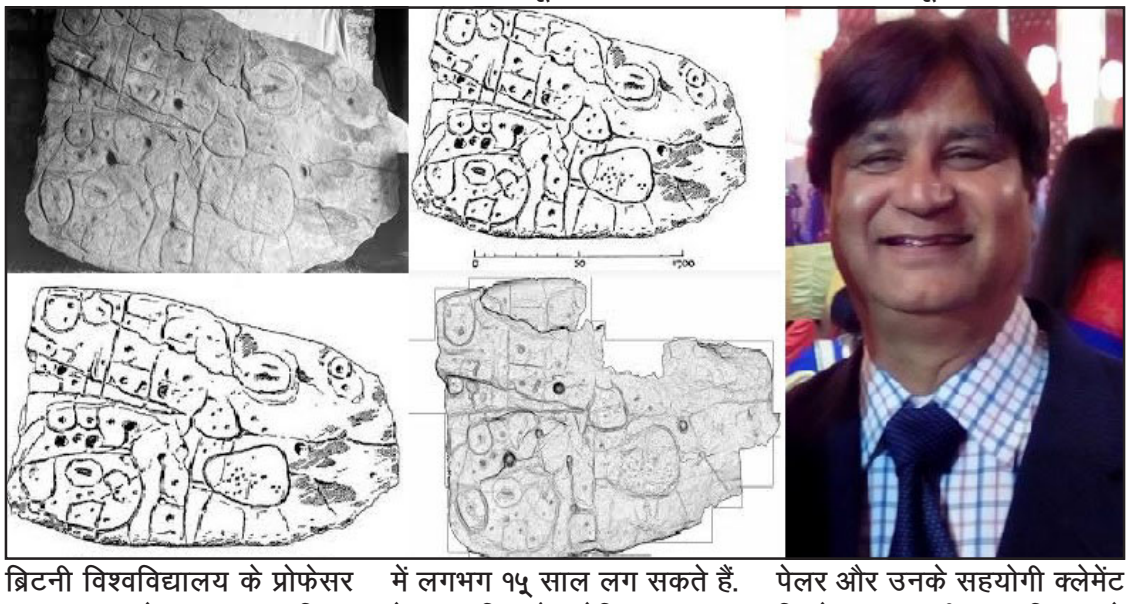

ब्रिटनी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर यवान पालर ने कहा, 'पुरातात्विक स्थलों को खोजने के लिए मानचित्रों का उपयोग करना एक अच्छा कदम हो सकता है. उन्होंने यह भी कहा, 'यह एक खजाने का नक्शा है. हालाँकि, शोधकर्ताओं को इस मानचित्र को पूरी तरह से समझने में लगभग १५ साल लग सकते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि यह नक्शा लगभग ३० किमी • २१ किमी के क्षेत्र को चिह्नित करता है, जिसका अर्थ है कि उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने और फिर उसे खोजने में बहुत समय लगेगा. सीएनआरएस रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर यवन पेलर और उनके सहयोगी क्लेमेंट निकोलस उस टीम का हिस्सा थे जिसने २०१४ में स्लैब को फिर से खोजा था. रहस्यमय चट्टान के रहस्यों को समझने के लिए फ्रांस और दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ भी पेलोर और निकोलस के साथ शामिल हुए. शोधकर्ताओं ने कहा कि सेंट–बेलेक स्लैब में बोल्ड राहतें और रेखाएं हैं जो पेरिस से लगभग ५०० किलोमीटर पश्चिम में ब्रिटनी क्षेत्र के हिस्से राउडुअलेक में नदियों और पहाड़ों को दर्शाती हैं. पत्थर पर छोटे–छोटे गड्ढे भी हैं, जिनके बारे में विशेषज्ञों का मानना है कि यह कब्रगाह या निवास का संकेत देते हैं. यह पत्थर पहली बार १६०० में फ्रांस में खोजा गया था, लेकिन फिर २०१७ तक महल के तहखाने में पड़ा रहा. इस पर बने रहस्यमयी निशान चार हजार साल तक रहस्य बने रहे. बाद में शोधकर्ताओं ने इस पत्थर पर बने रहस्यमय निशानों को समझने के लिए अध्ययन करना शुरू किया. आखिरकार अब उन्हें सफलता मिल गई है।

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में न्याय की मांग के लिए पहुंची दो महिलाएं : पुलिस में दर्ज किया मुकदमा

हाथरस । हाथरस में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में पहुंची दो महिलाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर

वायरल हो रहा है। उनमें से एक अपनी बहन की हत्या किए जाने की बात कहते हुए न्याय की गुहार लगा रही थी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए ३२ सेकंड के वीडियो में हरा कुर्ता पहनी एक महिला रोते और चिल्लाते हुए नजर आ रही है। वीडियो में वह कह रही है, मेरी बहन को मारा है, हमें न्याय दो। उस वक्त कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। वीडियो में एक अन्य महिला भी अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए हाथ हिलाते हुए नजर आ रही है। एक महिला पुलिसकर्मी उन्हें पीछे ले गई, जबकि मीडियाकर्मियों को उनकी तस्वीरें खींचते और वीडियो बनाते देखा गया। वीडियो को सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है। इस मामले पर जवाब देते हुए हाथरस पुलिस ने एक्स पर बताया कि इस मामले में एक अक्टूबर को पीड़िता के पति, ससुर और सास समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उनमें से पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। वैसे महिलाएं किस मामले में न्याय मांग रही थीं इस बारे में पुलिस ने कोई जानकारी साझा नहीं की है।

सौतेले बेटे की हत्या कर शव सीवर टैंक में छुपाने की आरोपी महिला समेत दो गिरफ्तार

गाजियाबाद। गाजियाबाद जिले के मोदी नगर इलाके में अपने ११ वर्षीय सौतेले बेटे की हत्या करने और उसके शव को घर के सीवर टैंक में

छुपाने के आरोप में एक महिला को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। मोदी नगर क्षेत्र के अपर पुलिस आयुक्त ज्ञान प्रकाश राय ने मंगलवार को बताया कि पुलिस को सोमवार को शिकायत मिली थी कि शादाब (११) नामक लड़का रविवार से लापता है। मामले की तफ्तीश के दौरान शक होने पर पुलिस ने उसके घर की सघन तलाशी ली तो सीवर टैंक के अंदर से शादाब का शव बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घर में मौजूद लोगों से पूछताछ की तो शादाब की सौतेली मां रेखा ने स्वीकार किया कि उसने अपनी सहेली पूनम की मदद से शादाब की हत्या की थी। राय के मुताबिक, शादाब रविवार को जब खेल कर घर वापस लौटा था तब रेखा ने पूर्व नियोजित साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी और उसका शव घर में ही बने सीवर टैंक में फेंक दिया। सूत्रों के अनुसार, रेखा शादाब के पिता राहुल सेन की दूसरी पत्नी थी और वह अपने सौतेले बेटे को पसंद नहीं करती थी। रेखा ने अपने पति राहुल और अन्य परिजन के सामने शादाब का अपहरण होने का दावा किया था।

सपा को कांग्रेस का सहयोग करना चाहिए : अजय राय

लखनऊ। मै एक आम और साधारण आदमी हूं। वह जो चाहें मुझे कह सकते हैं, मेरी लिए हर तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं कांग्रेस का छोटा

कार्यकर्ता हूं, लेकिन बीजेपी को हराना है तो सपा को कांग्रेस का सहयोग करना चाहिए। यह शब्द उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के हैं। उन्होंने यह बातें आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुये कही हैं। दरअसल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। इतना ही नहीं यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को लेकर अशोभनीय टिप्पणी कर दी थी। जिस पर अजय राय ने बिना अखिलेश यादव का नाम लिये कहा कि वह जो चाहें वैसे शब्दों का इस्तेमाल करें, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए उन्हें कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। हमने भी घोसी चुनाव में उनका समर्थन किया था।

भारत में कनाडाई राजनयिकों की समान संख्या सुनिश्चित करना अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन नहीं : विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली। भारत ने कनाडा के ४१ राजनयिकों की देश से वापसी को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन के रूप में 'पेश' करने की कनाडा की कोशिशों को शुक्रवार को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दो–तरफा राजनयिक समानता सुनिश्चित करना पूरी तरह से राजनयिक संबंधों को लेकर हुई वियना संधि के प्रावधानों के अनुरूप है। भारत की यह टिप्पणी कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली द्वारा भारत से राजनयिकों की वापसी की घोषणा के बाद आई है, जिसमें उन्होंने नयी दिल्ली की कार्रवाई को 'अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत' और राजनयिक संबंधों पर वियना संधि का उल्लंघन बताया था। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि समानता लाने के भारत के निर्णय के बारे में लगभग एक महीने पहले कनाडा को अवगत कराया गया था और इसे लागू करने की तारीख १० अक्टूबर थी, लेकिन इसे २० अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था क्योंकि समानता लागू करने के तौर–तरीकों पर कनाडाई पक्ष से परामर्श से काम किया जा रहा था। एक सूत्र ने कहा, ''बेंगलुरु, मुंबई और चंडीगढ़ में कनाडा के वाणिज्य दूतावासों में राजनयिक संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। भारत में अपने तीन वाणिज्य दूतावासों में कामकाज रोकने का कनाडा का फैसला एकपक्षीय है और समानता के क्रियान्वयन से संबंधित है।'' विदेश मंत्रालय ने कहा, ''हम समानता के कार्यान्वयन को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन के रूप में पेश करने के किसी भी प्रयास को खारिज करते

हैं।'' इस साल जून में खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने के कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोप के बाद दोनों पक्षों के बीच राजनयिक तनाव पैदा गया था औरपिछले महीने भारत ने कनाडा से अपने ४१ राजनयिकों को वापस बुलाने को कहा था। भारत ने साथ ही कनाडा के आरोपों को ढ़ता से खारिज कर दिया था। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा, ''हमने भारत में कनाडाई राजनयिकों की उपस्थिति के संबंध में १६ अक्टूबर को कनाडा सरकार द्वारा दिया गया बयान देखा है।''मंत्रालय ने कहा, ''हमारे द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति, भारत में कनाडाई राजनयिकों की बहुत अधिक संख्या और हमारे आंतरिक मामलों में उनका निरंतर हस्तक्षेप नयी दिल्ली और ओटावा में पारस्परिक राजनयिक उपस्थिति में समानता को वांछित बनाता है।'' विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने राजनयिक उपस्थिति में समानता सुनिश्चित करने के तौर–तरीकों पर पिछले महीने कनाडाई पक्ष के साथ विस्तृत चर्चा की थी। मंत्रालय ने कहा, ''राजनयिक उपस्थिति में समानता को लागू करने का हमारा कदम वियना संधि के अनुच्छेद ११.१ के तहत पूरी तरह से सुसंगत है।''इसके साथ ही मंत्रालय ने वियना संधि के अनुच्छेद का भी उल्लेख बयान में किया है। जोली ने बृहस्पतिवार को कहा था कि राजनयिक समानता के अपने 'अनुचित' अनुरोध में, भारत केवल २१ राजनयिकों और उनके परिवारों को अपनी राजनयिक स्थिति बनाए रखने की अनुमति देगा।ओटावा में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, ''इसका मतलब है कि ४१ कनाडाई राजनयिकों और उनके ४२ आश्रितों को एक मनमानी तारीख पर 'इम्युनिटी' छिनने का खतरा था, और इससे उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।

मकान में आग लगने से तीन लोगों की मौत, दो घायल

बदायूं। बदायूं में उझानी कस्बे के मोहल्ला गद्दी टोला में बृहस्पतिवार रात एलपीजी गैस सिलेंडर में लगी आग ने एक मकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे एक परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओ पी सिंह ने बताया कि इस हादसे में सुखबीर मौर्य (३५) और उसके दो बेटों– गोपाल मौर्य (आठ) एवं यश (छह) की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और मां गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्होंने बताया कि उझानी थाना क्षेत्र में स्थित मकान में खाना पकाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई थी और फिर इस आग ने पूरे मकान को चपेट में ले लिया। उन्होंने बताया कि घायलों को इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मकान के भूतल पर रहने वाले मृतक के बड़े भाई भूप सिंह के मुताबिक, खाना पकाते समय रात करीब नौ बजे गैस सिलेंडर में आग लगने पर सुखबीर की पत्नी के मदद के लिए शोर मचाया, जिसके बाद हर कोई ऊपर की मंजिल की ओर भागा, जहां सुखबीर और उसके दो बेटे कमरे में फंसे थे। भूप सिंह ने बताया कि सुखबीर ने जलते सिलेंडर को बाहर फेंकने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका और आग पूरे कमरे में फैल गई। पुलिस ने बताया कि पुलिस दल रात में घटनास्थल पर पहुंचा और फारेंसिक टीम को भी बुलाया गया। इस मामले में जांच जारी है।

हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में नागा साधु की गला घोंटकर हत्या : दो शिष्य गिरफ्तार

अयोध्या। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में एक नागा साधु की बुधवार देर रात गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि मृतक की पहचान साधु राम सहारे दास (४०) के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि बुधवार देर रात गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने बताया कि मृतक के गले पर एक गहरा निशान पाया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में मृतक साधु के दो शिष्यों अंकित दास और ऋषभ शुक्ला को गिरफ्तार किया है। हनुमान गढ़ी मंदिर के महंत (पुजारी) राम चरण दास ने कहा, हत्या करने के बाद हमलावरों ने कमरे के दरवाजे बंद कर दिए और भाग गए। इस हत्या की जानकारी आज सुबह करीब छह बजे मिली जब उनके कमरे के दरवाजे नहीं खुले।'' उन्होंने बताया, आमतौर पर वह सुबह जल्दी उठ जाते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जब कुछ साधुओं ने उन्हें आवाज दी तो कोई जवाब नहीं मिला। जब उनके कमरे का दरवाजा खोला गया तो अंदर साधु राम सहारे दास का शव पाया गया और जमीन पर चारों तरफ खून पड़ा था। अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आर के नैय्यर ने बताया कि हत्या के संबंध में महंत राम चरण दास की ओर से शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें उन्होंने मृतक के दो शिष्यों अंकित दास और ऋषभ शुक्ला पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने पीटीआई– को बताया कि मृतक साधू वर्ष १९९१ से अपने बचपन के दिनों से हनुमानगढ़ी में रह रहा था। वह हनुमानगढ़ी में एक आश्रम का महंत था जहां वह ८–१० बच्चों को शिक्षा दिया करता था।

जनता को दिवाली का तोहफा, १० प्रतिशत तक घटेगा राजधानी बसों का किराया!

लखनऊ। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी की बसों में सफर वाले यात्रियों को दिवाली का तोहफा देने वाले हैं। योगी सरकार राजधानी बसों का किराया १० प्रतिशत कम करने जा रही है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से बस यात्रियों को सीधा लाभ होगा। इसी मामले को लेकर व यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए यूपी परिवहन निगम के अध्यक्ष व प्रमुख सचिव वेंकटेश्वर लू की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक हुई। वहीं जानकारी देते हुए परिवहन विभाग के जीएम मनोज पुंडीर ने बताया कि राजधानी लखनऊ में संचालित हो रहीं

बसों का किराया १० प्रतिशत कम करने का फैसला परिवहन निगम की बैठक में लिया गया है। आदेश जारी होने के बाद यह लागू भी हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जनता को पहले १४३ पैसेध्किमी के हिसाब से किराया पड़ता था, लेकिन अब १३३ पैसेध्किमी के हिसाब से किराया पड़ेगा। बता दें कि बसों का किराया १० प्रतिशत कम होने से कम से कम १० रुपये और ज्यादा से ज्यादा ८० रुपये की कमी आएगी। यह किराया केवल अ रेंज कलर की राजधानी बसों में ही कम होगा। गौरतलब है कि साधारण बसों से राजधानी बसों का किराया १० प्रतिशत ज्यादा था, जिसमें १० प्रतिशत कमी का निर्णय हुआ है।

अगले वर्ष से कन्या सुमंगला के तहत देंगे 25 हजार रुपए : योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सेठ फूलचंद बांग्ला पीजी क लेज में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने १७७.२६ करोड़ रुपए

की २१४ विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए संवाद किया। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे बंद हो गए हैं। खुशी के साथ यहां त्योहार मनाए जा रहे हैं। आज सरकार की सभी योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं डबल इंजन की सरकार के एजेंडे में हैं। पिछले साढ़ें नौ साल के अंदर हमने नए भारत का दर्शन किया है। जिसमें किसी के साथ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उनको आगे लाया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि बेटा और बेटी में कोई भेदभाव न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत मिलने वाली धन राशि को हमारी सरकार ने बढ़ा दिया है। इसके तहत मिलने वाली १५ हजार की राशि को बढ़ाकर हमने २५ हजार कर दिया है। योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की सोच विकास की है। इसी के अंतर्गत सरकार सड़क, पेयजल, स्टेडियम सहित अपने तमाम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। हम चाहते हैं कि जैसे एशियाई खेलों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेटियों ने कमाल किया। वैसे ही हाथरस जनपद में भी बेटियां आगे बढ़ें।

गठबंधन सहयोगी सपा के पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल

लखनऊ। इंडिया गठबंधन के सहयोगी समाजवादी पार्टी को एक और झटका कांग्रेस ने दिया है। सपा से पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी और पूर्व विधायक गाजीपुर पशुपति नाथ राय ने बुधवार को अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बुधवार को दोनों नेताओं को सदस्यता दिलाई। पूर्व विधायक पशुपतिनाथ राय जनपद गाजीपुर के मोहम्दाबाद सीट से विधायक रहे हैं। गयादीन अनुरागी हमीरपुर से विधायक रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भाजपा की जनविरोधी नीतियों से त्रस्त प्रदेश की जनता कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगांहों से देख रही है। पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी ने कहा कि प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है। सरकार अपराधियों को बचा रही। कांग्रेस ने हमेशा दलितों का सम्मान दिया। पशुपतिनाथ राय ने कहा कि भाजपा अपनी जनसेवा के विचार को छोड़ चुकी है, अब सिर्फ उद्योगपतियों के लिए भाजपा काम कर रही है। कांग्रेस ही देश की उम्मीद है।

हमारे अन्य प्रतिनिधि

lt; ckt ib

lhrkiqj

ek-9935160370

प्रियंका त्रिपाठी

नई दिल्ली

विधिक सलाहकार

lj'k ukjk;.k feJ

क्षेत्रीय सम्पादक

lkjHk dqekj] fcgkj

ek-09386075289

मो० अरशद

C;jks phQ

eÅ

अलग हो रहे हैं शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा किया ऐलान

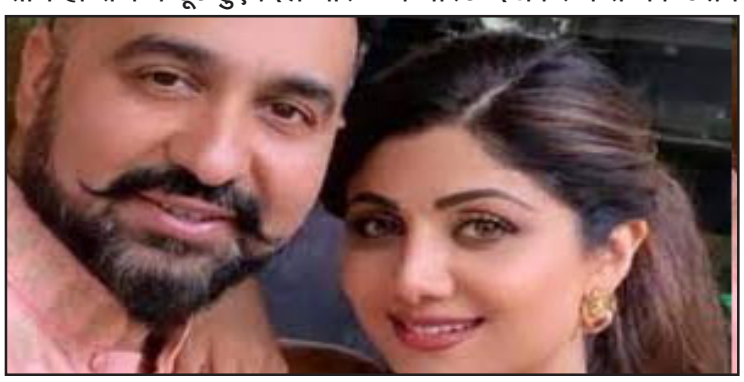

मुम्बई। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा अपनी निजी जिंदगी को लेकर अक्सर लाइमलाइट में रहते हैं। हाल ही में राज ने अपनी डेब्यू फिल्म यूटी ६६ की अनाउंसमेंट की है। इस फिल्म से राज एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। फिल्म के प्रमोशन के बीच राज ने एक ऐसा पोस्ट शेयर कर दिया है जिसे देखकर फैंस चौंक गए हैं। जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह शिल्पा से अलग हो रहे हैं। दरअसल, राज कुंद्रा ने आधी रात को अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट शेयर किया, जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी। ट्वीट में राज ने लिखा, ष्हम अलग हो गए हैं। आपसे अनुरोध है कि इस कठिन दौर में हमें कुछ समय दें।ष् इसके साथ ही राज ने टूटे हुए दिल और

हाथ जोड़ने वाले इमोजी भी बनाए। बता दें कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने नवंबर २००९ में शादी की थी। उनकी शादी को १४ साल पूरे होने वाले हैं। हर मुश्किल समय में दोनों एक–दूसरे का साथ देते नजर आते हैं। अब ये पोस्ट देखकर फैंस को टेंशन हो गई है। वहीं कुछ लोग इसे प्रमोशनल बता रहे हैं। इस पोस्ट के सामने आने के बाद सवाल उठने लगे कि क्या राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी अलग हो गए हैं। कई लोग इसे प्रमोशन बता रहे हैं। एक यूजर ने पूछा, श्अलगाव मतलब, तलाक?श् एक ने कहा, श्घटिया नौटंकी।श् एक यूजर ने लिखा, श्मूवी पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं।श् एक ने कहा, श्अलगाव मतलब, मास्क का राज कुंद्रा से अलगाव।श् इसी तरह कई लोग राज कुंद्रा को जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। राज कुंद्रा की आगामी फिल्म श्यूटी ६९श् उनकी आपबीती की कहानी बयां करती फिल्म है। शाहनवाज अली द्वारा निर्देशित राज की फिल्म का ट्रेलर बीते दिनों रिलीज हुआ था। फिल्म ३ नवंबर २०२३ को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें राज ही लीड हीरो हैं।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।
आर.एन.आई
UPHIN/2010/32566

रोहित शेट्टी की 'सिंघम अगेन' में नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ

मुंबई। रोहित शेट्टी का पुलिस जगत टाइगर श्रॉफ के शामिल होने से बड़ा होने जा रहा है, जिसमें अभिनेता फिल्म निर्माता की आगामी फिल्म 'सिंघम अगेन' में नजर आएंगे। 'हीरोपंथी', 'बागी' और 'वॉर' जैसी फिल्मों में मुख्य किरदार निभाने वाले श्रॉफ 'सिंघम अगेन' में एसीपी सत्या की भूमिका निभाएंगे। इस फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है। शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर अभिनेता की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, " विशेष कार्य बल अधिकारी एसीपी सत्या से मिलिए, ये सच की तरह अमर हैं। दल में स्वागत है... टाइगर।" शेट्टी के इस पोस्ट पर श्रॉफ ने भी जवाब दिया, वहीं अजय देवगन ने भी टाइगर का फिल्म में स्वागत किया है। 'सिंघम अगेन' देवगन अभिनीत 'सिंघम' श्रृंखला की तीसरी फिल्म है जिसकी शुरुआत पहली फिल्म 'सिंघम' से वर्ष २०११ में हुई थी और उसके बाद 'सिंघम रिटर्न्स' आई। शेट्टी के पुलिस जगत में दो फिल्में और हैं जिसमें से एक

रणवीर सिंह की वर्ष २०१८ में आई 'सिम्बा' और दूसरी वर्ष २०२१ में रिलीज हुई अक्षय कुमार की 'सूर्यवंशी' है। 'सिंघम अगेन' में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी हैं जो पुलिस अधिकारी शक्ति शेट्टी की भूमिका निभाएंगी। उनके किरदार को इन पुलिस कलाकारों में सबसे क्रूर और हिंसक कहा जाता है। 'सिंघम अगेन' में सिंह यानी संग्राम भालेराव उर्फ सिम्बा भी नजर आएंगे। वहीं अवनि कामत की भूमिका निभाने वाली करीना कपूर खान भी तीसरे भाग में वापसी कर रही हैं।

सम्पादक
आरती पाण्डेय
मो.9415087228
9889745884. 9807059191. 9026560178
Email-
adbhutsamachar@yahoo.in
adbhut_samachar@rediffmail.com

सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक